प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

26.08.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800 बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा जिले में एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं में विस्थापित हुए परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एनएचपीसी को विस्थापित परिवारों की सूची भी दी है। सरकार का प्रयास है कि इन परिवारों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैय्यर के मूल और डॉ. हंसराज के अनुपूरक सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिले में स्थापित बैरा स्यूल बिजली परियोजना 40 साल पूरा कर चुकी है। सरकार इसे अधिकृत करेगी और इसके लिए परियोजना प्रबंधन को नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल के अधिकारों के साथ खड़ी है और दिसंबर माह में सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में जमीन की सेटलमेंट की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश विधानसभा में आज राज्य में उद्योगों को पूर्व भाजपा सरकार द्वारा दी गई कथित रियायतों के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उद्योगों को रियायतें दिए जाने के मुद्दे पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नारेबाजी हुई और तीखी नोक–झोंक के बीच विपक्षी भाजपा ने सदन से वाकआउट किया। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में दखल देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ में कुछ उद्योगों को सभी नियमों को ताक पर रखकर न केवल जमीन का आवंटन किया, बल्कि अन्य सुविधाएं देकर प्रदेश के खजाने पर बेवजह बोझ डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कंपनियों को जहां एक रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से हजारों बीघा जमीन दे दी गई, वहीं, बिजली भी 10 वर्षों के लिए तीन रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देने का करार किया गया। जबकि प्रदेश खुद सर्दियों में छह रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदता है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर स्टांप ड्यूटी में शतप्रतिशत की छूट दी गई। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि यह कस्टमाइज पैकेज जनता के पैसे को लुटाने का पैकेज था। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि सरकार इस पैकेज की सारी जानकारी जुटाएगी और प्रदेश की संपदा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने इन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दी गई छूट के फैसले पर फिर से विचार करने की बात भी कही।

जयराम ठाकुर

विधानसभा से वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय राज्य को मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क मिले, लेकिन मौजूदा सरकार उद्योग बचाने में पूरी तरह विफल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में कोई बड़ा उद्योग प्रदेश में स्थापित नहीं हुआ।